

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

३३

प्रकरण क्रमांक : 771-दो/2006 निगरानी - विरुद्ध - आदेश दिनांक 30-1-06  
पारित द्वारा - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक  
414/2004-05 अपील

1- प्रहलाद पुत्र बट्टी धाकड़  
2- रामदयाल पुत्र लालू धाकड़  
निवासी ग्राम दुलारा तहसील पोहरी  
जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश

---आवेदकगण

विरुद्ध  
श्रीमती कान्ति पत्नि रामस्वरूप धाकड़  
ग्राम दुलारा तहसील पोहरी  
जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश

---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस०पी०धाकड़)

आ दे श

( आज दिनांक 6 - 2 - 2019 को पारित )

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक  
414/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-1-2006 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व  
संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि अनावेदक ने नायब तहसीलदार पोहरी के समक्ष  
पार्शना पत्र प्रस्तुत कर मांग रखी कि ग्राम दुलारा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1237/1 रकबा  
8 बीघा उसके स्वामित्व की राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है इसी से लगी भूमि सर्वे क्रमांक

1237/2 रकबा 13 वीघा 12 विसवा महिला भागरथी की , 1237 रकबा 5 वीघा 9 विसवा प्रह्लादी की, सर्वे क्रमांक 12450 रकबा 5 वीघा 9 विसवा रामदयाल की बंदोवस्त के पूर्व दर्ज रही है किन्तु बंदोवस्त के समय नये सर्वे नंबर बनाने के दौरान स्थल परिवर्तन करके उसकी भूमि अन्य की भूमि में मिला दी गई , जिसे सुधार कर यथावत् किया जावे। नायब तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 3/1998-99 अ-5 पंजीबद्ध किया तथा जांच एवं सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30-12-2002 पारित किया तथा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार रिकार्ड दुरुस्ती के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी पोहरी ने प्रकरण क्रमांक 12/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-11-2004 से अपील स्वीकार की तथा सहायक बंदोवस्त अधिकारी शिवपुरी के जांच प्रतिवेदन दिनांक 31-12-93 को आदेश का अंग मानते हुये नक्शा/रकबा दुरुस्त करना निर्णीत किया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 414/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-1-2006 से अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।


3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा

उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों , उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के क्रम में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह सही है कि बंदोवस्त के पूर्व अनावेदक का रकबा 1-60 हैक्टर रहा है , बंदोवस्त के दौरान नक्शे की आकृति में कम हो जाने से उसने म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 89 के अंतर्गत आवेदन तहसील न्यायालय में दिया है, जिसमें कमी पाकर रकबा पूरा किया गया है। आवेदकगण की भूमि का रकबा बंदोवस्त के पूर्व दोनों का रकबा 1-14 हैक्टर एवं 1-14 हैक्टर रहा है किन्तु बंदोवस्त के दौरान त्रुटिवश दोनों का रकबा बढ़ाकर 1-60 हैक्टर एवं 1-60 हैक्टर हो गया जो पूर्व के रकबा 1-14 हैक्टर से अधिक हो गया एवं अनावेदक के रकबे से बढ़े हुये रकबे की पूर्ति होना जांच में पाया गया। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी पोहरी ने स्थल जांच के बाद आदेश

पारित करके दोनों आवेदकों का रकबा 1-14 हैक्टर एवं 1-14 हैक्टर बराबर कर दिया जिसके कारण अनावदेक के रकबे की भी पूर्ति हो जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं हुआ है। अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के प्रकरण क्रमांक 12/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-11-2004 तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 414/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-1-2006 में निकाले गये निष्कर्षों से परिलक्षित है कि दोनों ही न्यायालयों के निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 414/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-1-2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

  
(एस.एस.अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर